P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- XI* April- 2016

सशक्त कार्यदल (EAG) और गैर सशक्त कार्य दल (NEAG) राज्यों की सामाजिक–आर्थिक विषमता का तुलनात्मक विश्लेषण

राहुल श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज,
गोरखपुर

सारांश

भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक दश है, यहाँ 1 अरव 21 करोड़ से अधिक लोग 35 राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। उनके सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है। देश की कुल जनसंख्या को सशक्त कार्यदल (EAG-Empowerd Action Group) राज्य और गैर सशक्त कार्यदल (NEAG- Non Empowerd Action Group) राज्य में आसानी से बाटा जा सकता है। इन राज्यों की सामाजिक विषमताओं का आकलन, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि राज्यों के मध्य भेदात्मक लिंग–अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन तथा साक्षरता दरों में वृद्धि के माध्यम से किया गया है। आर्थिक घटक के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का प्रादेशिक स्तर पर आकलन कर उपरोक्त वर्गीकृत दो कार्यदल राज्यों की आर्थिक स्थिति के भेदात्मक विश्लेषण एवं भारत के सापेक्ष उसकी हिस्सेदारी का अध्ययन करने के लिए किया गया है।

मुख्य शब्द : सशक्त एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्य, ग्रामीण जनसंख्या,साक्षरता दर, लिंगानुपात, शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय

प्रस्तावना

अध्ययन हेतु आकडों का संकलन जनगणना 1991 से 2011 तक लिया गया है साथ ही साथ विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों का अनुपातिक एवं माध्य विश्लेषण किया गया है। विभिन्न लेखों पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त सन्दर्भ का प्रयोग भी अध्ययन पद्धति में किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य सशक्त कार्यदल राज्यों तथा गैर सशक्त कार्य दल के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे–जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, श्रम शक्ति का ग्रामीण क्षेत्रो से वाह्य पलायन तथा औद्योगिकरण पर पड़ने वाले अत्यधिक दवाब, आर्थिक असमानताओं और उसको प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी प्राप्त करन है। जनांकिकी सामूहिक रुप से मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास तथा गतिशीलता का अध्ययन करता है।[1] दश की कुल जनसंख्या को सशक्त कार्यदल (EAG- Empowerd Action Group) राज्यों में आठ राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तोसगढ़ और उड़ीसा को चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त गैर सशक्त कार्यदल (NEAG- Non Empowerd Action Group) राज्यों में उपरोक्त आठ राज्यों को छोड़ कर शष भारत की जनसंख्या को शामिल किया जा जाता है। सन् 1951–2011 के मध्य ई0ए0जी0 राज्यों की कुल जनसंख्या का अंश भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 45 प्रतिशत के मध्य रहा है। जनांकिकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन व उनमें परिवर्तन के घटकों जो कि जन्म, मृत्य, क्षेत्रीय प्रवास एवं सामाजिक गतिशीलतका के रुप में जाना जाता है।[2] कुछ जनांकिकी विश्लेषकों ने यह स्पष्ट किया की जनांकिकी वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार संरचना तथा वितरण में ही नही बल्कि समय–समय पर इन तथ्यों के परिवर्तन और परिवर्तन के कारणों से भी सम्बन्ध रखता हैं।

सशक्त कार्यदल (EAG) और गैर सशक्त कार्यदल (NEAG- Non Empowerd Action Group) राज्यों की सामाजिक विषमता

स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में हमे यह तथ्य देखने को मिलता है कि उन्नीसवी शताब्दी में वृद्धि दर पूर्व के वर्षों की तुलना में संतोषजनक है किन्तु वर्तमान में गैर सशक्त कार्यदल राज्यों की तुलना में सशक्त कार्यदल राज्यों की जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है। जनता में जागरुकता में कमी, स्वास्थय सुविधाओं का प्रचार एवं प्रसार न होना

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- XI* April- 2016

और साथ ही साथ केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्यों सरकारों की उदासीनता का परिणाम है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को पृथक–पृथक अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि 1951 से 1975 के मध्य भारत, सशक्त कार्यदल एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों में ग्रामीण जनंसख्या की वृद्धि दर में अधिक अन्तर नही था किन्तु 1981 के बाद से सशक्त कार्यदल राज्यों में सापेक्षिक रुप से जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट का संकेत मिल है यह इस बात का परिचायक है सशक्त कार्यदल राज्यों में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुर आवश्यकता है। जागरुकता हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी तन्त्र का क्रियान्वयन आवश्यक है।

भारत सशक्त कार्यदल (EAG) एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों (NEAG) की ग्रमीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (जनगणना–2011)

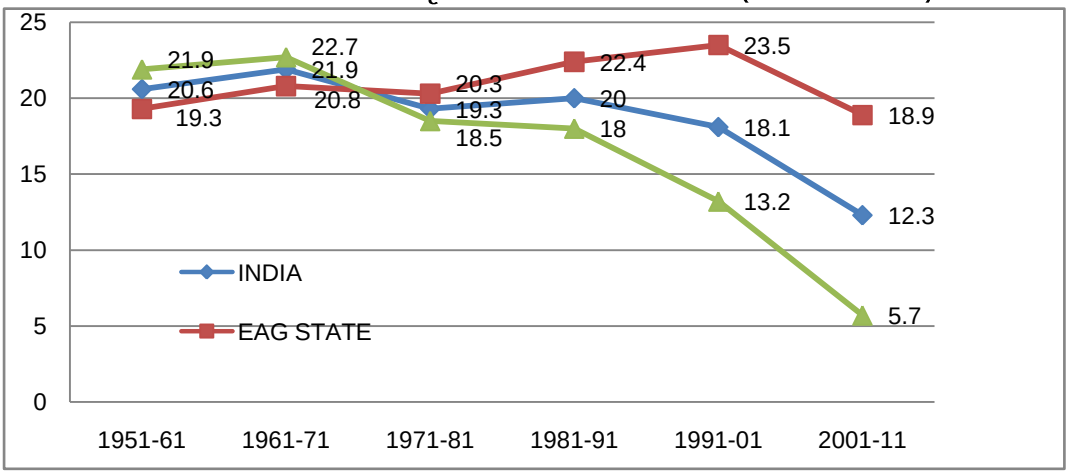

1951 से 2011 के मध्य शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के द"ाकीय वृद्धि के आकड़े हमें इस बात का बोध कराते है कि 1971 तक स"ाक्त कार्यदल राज्यों, गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों और समग्र रुप से भारत में जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में समान अनुपात से बढ़ रही थी किन्तु 1971–2011 के मध्य स"ाक्त कार्यदल राज्यों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि सापेक्षिक रुप से अधिक रही है इसमें भी वि"ोष रुप से 1971 से 1981 के मध्य यह स्थिति ज्यादा भयावह हो गयी है। 2001 के बाद हमें पुनः प्रारम्भिक स्थिति देखने को मिली है इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वै"वीकरण के बाद स"ाक्त कार्यदल राज्यों से कार्य"ाील जनसंख्या का पलायन लगातार बड़े शहरों की ओर हो रहा है जिसे नियंत्रित करने के लिए रोजगार परक उद्योगों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नितान्त आव"यकता है।

भारत, सशक्त कार्यदल (EAG) एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों(NEAG) की शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (जनगणना–2011)

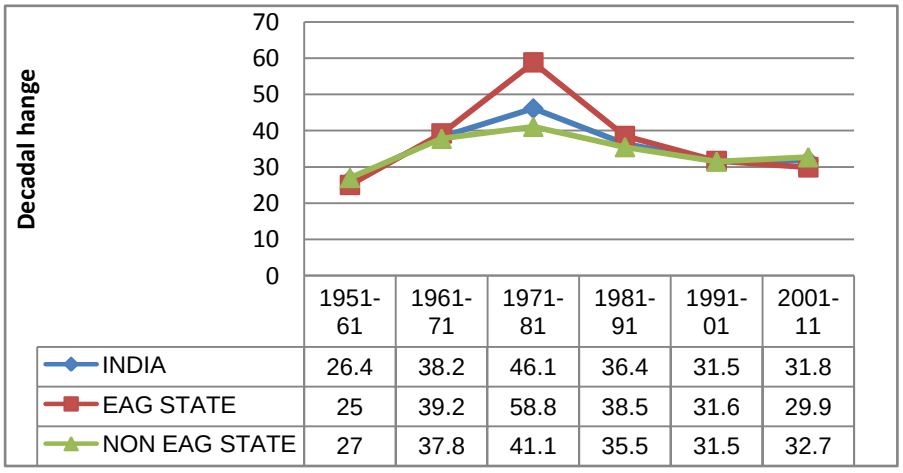

	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91	1991-01	2001-11
INDIA	26.4	38.2	46.1	36.4	31.5	31.8
EAG STATE	25	39.2	58.8	38.5	31.6	29.9
NON EAG STATE	27	37.8	41.1	35.5	31.5	32.7

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- XI* April- 2016

स"ाक्त कार्यदल राज्यों, गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों और भारत के लिंगानुपात का वि"लेषण करना भी आव"यक हो जाता है क्योंकि लिंगानुपात किसी वि"ाष्ट समय पर किसी दे"ा स्थान व जाति वि"ाष के स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को प्रदर्"ात करता है।[3] लिंगानुपात यह इंगित करता है कि किसी प्रदे"ा अथवा दे"ा में ि"ा"ाु स्त्री अनुपात कितना अच्छा है। स"ाक्त कार्यदल राज्यों में 1951 से 2011 के मध्य यह अनुपात भारत एवं गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों से सदैव ही कम रहा है जो इन आठ वि"ाष्ट राज्यों में कमजोर ि"ा"ाु स्त्री अनुपात का परिणाम है। इसके इतर गैर स"ाक्त

कार्यदल राज्यों में लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से हमे"ाा अधिक रहा है जो इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों में गर्भवती महिलओं एवं नवजात ि"ा"ाुओं के चिकित्सा सुविधाओं उनके पालन पोषण एवं भ्रूण हत्या के प्रति लोगों में पूर्ण जागरुकता है ऐसी ही परिस्थिति कायम करके हम स"ाक्त कार्यदल राज्यों में लिंगानुपात को संतुलित कर सकते है।

भारत, सशक्त कार्यदल (EAG) एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों (NEAG) के लिंगानुपात 1991 से 2011 के मध्य (जनगणना–2011)

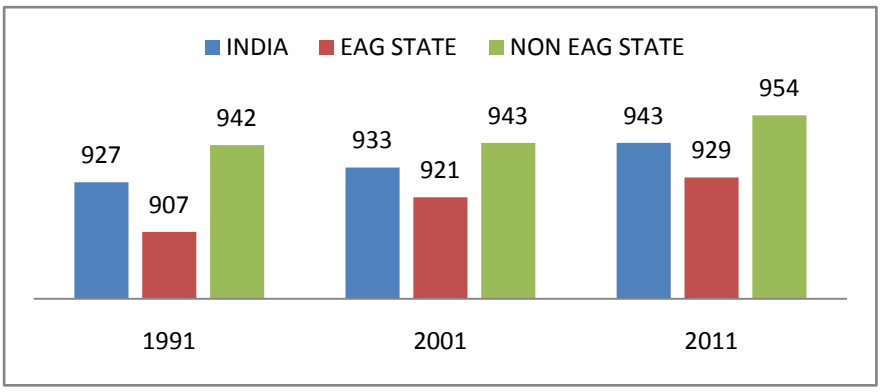

मानव संसाधन उत्पादन मात्र एक ऐसा संसाधन है जो अन्य उपलब्ध संसाधनों की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है इसी को ध्यान में रखकर हम अनुकूलतम जनसंख्या द्वारा अधिकतम आय प्राप्त करना चाहते है।[4] वर्तमान में अधिकक्य आय अर्जन हेतु यह स्वाभाविक है कि कार्य"ाील जनसंख्या का नगरीकरण हो क्योंकि कृषि उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता क्रमिक रुप से घट रही है। जब तक ग्रामीण स्तर पर हम रोजगार का सृजन नही करेगे जनसंख्या का पलायन नगरीय क्षेत्र की ओर स्वाभाविक है श्रम शक्ति को उत्पादक एवं उसमें पूँजी संचयन की शक्ति उत्पन्न करने के लिए उसका औद्योगिक क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण आव"यक है।[5] स"ाक्त कार्यदल राज्यों की जंनाकिकी हमें इस बात का बोध कराते है कि ऐसे राज्यों में नगरीय जनसंख्या की कमी है जिसके कारण कम उत्पादक भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। विगत 65 वर्षों में इन आठ राज्यों के नगरीय जनसंख्या का अनुपात धीमी गति से बड़ा है सपेक्षतया गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है इन तथ्यों का सन्दर्भ लेते हुए हम यह कह सकते है कि अभी भी स"ाक्त कार्यदल राज्यों में कृषि पर लोगों की निर्भरता जाता है।

भारत, सशक्त कार्यदल (EAG) एवं गैर सशक्त कार्यदल राज्यों(NEAG) के ग्रामीण जनसंख्या अनुपात (जनगणना 2011)

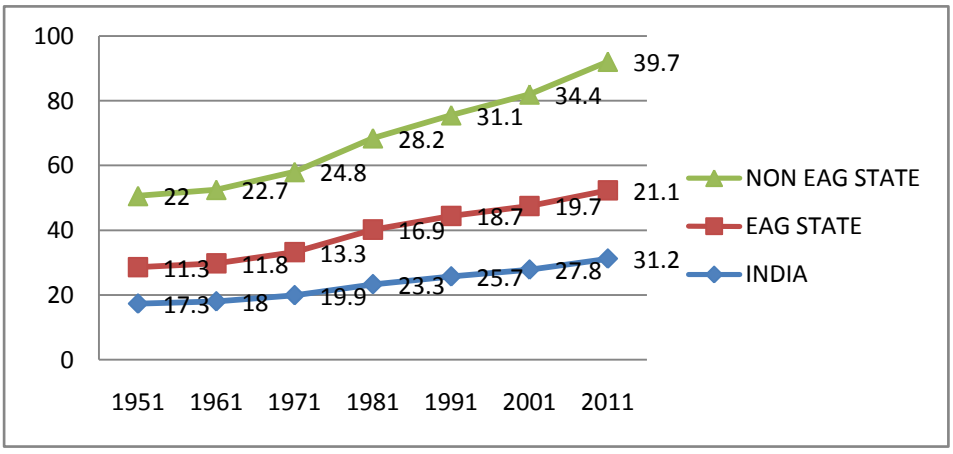

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- XI* April- 2016

किसी भी दे"ा अथवा प्रान्त में साक्षरता का अनुपात यह द"र्ाता है कि प्राथमिक f"ाक्षण संस्थाओं का कितना प्रभावी ढग से विस्तार हुआ है और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों के पलायन को हम कितने नियंत्रित कर पाये है ऐसे परिस्थिति का अवलोकन जब हम मुख्यतया स"ाक्त कार्यदल राज्यों पर करते है क्योंकि गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों में साक्षरता का स्तर स्वभाविक रुप से पहले से अधिकर रहा है दे"ा की वर्तमान औसत साक्षरता दर 73.0 प्रति"ात से है विगत 10 वर्षों में पूरे दे"ा साक्षरता प्रवृति में जहाँ 36.16 प्रति"ात की वृद्धि हुई है वही बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदे"ा में इस अवधि में साक्षरता की प्रवृति में क्रम"ाः 68.77 प्रति"ात, 55.62 प्रति"ात, 51.08 प्रति"ात वृद्धि देखने को मिली है जो संतोषजनक है। राजस्थान और अन्य स"ाक्त कार्यदल राज्यों में साक्षरता की वृद्धि दर अभी भी आ"ाानुरुप नही है। अतः हमें शैक्षणिक गुणवक्ता में सुधार कर, बच्चों में f"ाक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करकें, f"ाक्षा की लागत में कमी करके उससे समान बच्चों तक पहुचाने की जिम्मेदारी सभी को उठानी होगी।

सशक्त कार्यदल (EAG) की साक्षरता दर–वर्ष 2001 से 2011 के मध्य
(जनगणना 2011)

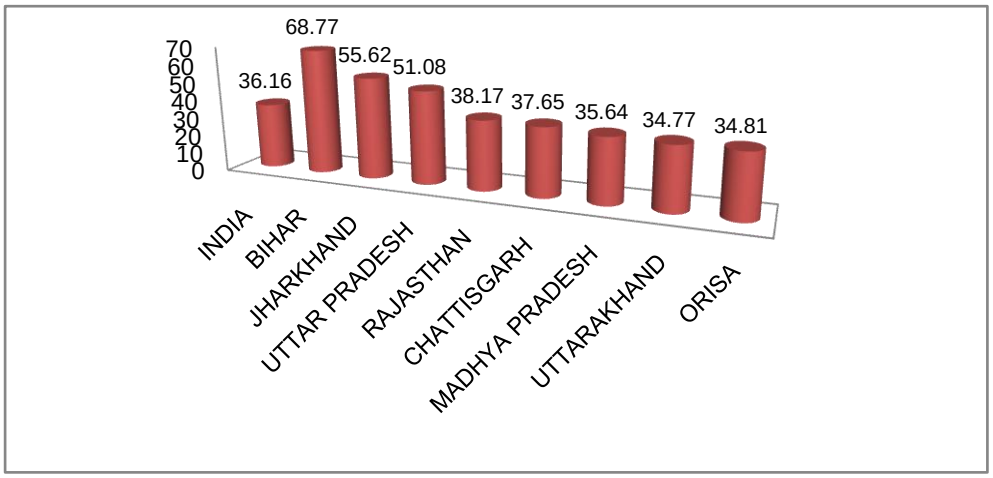

सशक्त कार्यदल (EAG) और गैर सशक्त कार्यदल (NEAG) राज्यों की आर्थिक भिन्नताएँ

आर्थिक संकेतकों के रूप में मुख्यतः निबल, घरेलू राज्य उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर स"ाक्त कार्यदल और गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों के मध्य आर्थिक असमानताओं का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है। किसी दे"ा द्वारा एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध संसाधनों (भौतिक एवं अभौतिक) द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय के रूप में मापते हैं। वर्ष–2004 से 2014 के मध्य स"ाक्त कार्यदल राज्य अर्थात् बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदे"ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदे"ा और उत्तराखण्ड का निबल घरेलू राज्य उत्पाद (Net State Domestic Product) का आकलन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि के मध्य भारत के निबल घरेलू उत्पाद में इन आठ राज्यों की हिस्सेदारी मात्र 25–26 प्रति"ात ही रही है। गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों की हिस्सेदारी भारत के निबल घरेलू उत्पाद में 74–75 प्रति"ात प्राप्त हुयी है। चयनित आठ राज्यों में भी नव गठित राज्यों (झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल) में अध्ययन अवधि के दौरान निबल घरेलू राज्य उत्पाद की कमिक वार्षिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कमी रही है। बिहार, मध्य प्रदे"ा एवं उत्तर प्रदे"ा में निबल घरेलू राज्य उत्पाद अध्ययन अवधि के दौरान स्वाभाविक रूप से बढ़े हैं। यदि हम निबल घरेलू राज्य उत्पाद के आधार पर गैर स"ाक्त राज्यों की तुलना स"ाक्त कार्यदल राज्यों से करते हैं तो मोटे तौर पर यह हम यह कह सकते हैं कि भारत के निबल राष्ट्रीय आय में गैर स"ाक्त राज्यों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत सदैव ही अधिक रही है। इसमें भी आन्ध्र प्रदे"ा, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र राज्य ज्यादा उत्कृष्ट योगदान देते हैं। सापेक्षिक रूप से जब हम निबल घरेलू राज्य उत्पाद के वार्षिक वृद्धि दर पर ध्यान देते हैं तो गैर स"ाक्त राज्यों एवं स"ाक्त राज्यों के मध्य कोई वि"ोष अन्तर दिखाई नहीं देता है। भारत के निबल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर अध्ययन अवधि के दौरान 16–17 प्रति"ात के मध्य आंकी गयी है और इसी के समतुल्य स"ाक्त कार्यदल राज्यों और गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों की निबल घरेलू राज्य उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर भी प्राप्त हुयी है।

निबल घरेलू राज्य उत्पाद (वर्तमान मूल्य 2004–05 के आधार पर)

प्रदेश	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिहार	70167	91331	102853	129690	149028	183970	230843
झारखण्ड	53056	58512	74388	76234	87112	1000112	113114
मध्यप्रदेश	99940	127663	142917	175503	202652	231355	281812
छत्तीसगढ़	41367	57536	69348	82809	86045	102918	118762
उड़ीसा	67987	87921	111109	127516	141318	168403	194869

राजस्थान	112636	151426	172250	203939	231963	286008	325266
उ0प्र0	231029	296767	335810	392771	463382	536297	609538
उत्तरांचल	22288	32670	40279	48616	61263	71264	82415
सशक्त राज्य	698470 (26.34)	903825 (25.57)	1048754 (25.61)	1237078 (26.11)	1422763 (26.19)	1680327 (26.24)	1956614 (26.56)
गैर सशक्त राज्य	1953103 (73.66)	2630721 (74.43)	3048436 (74.36)	3501292 (73.89)	4010825 (73.81)	4723612 (73.76)	5411604 (73.44)
भारत	2651573	3534547	4097390	4738370	5433588	6403939	7368223

() यह भारत के सापेक्ष प्रतिशत अनुपात को दर्शाता है।

निबल घरेलू राज्य उत्पाद की औसत वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य 2004–05)

प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिहार	23.18	12.62	26.09	14.91	23.45	25.48
झारखण्ड	9.86	27.13	2.48	14.27	14.93	12.98
मध्यप्रदेश	16.47	11.95	22.80	15.47	14.16	21.81
छत्तीसगढ़	26.00	20.53	19.41	3.91	19.61	15.39
उड़ीसा	19.54	26.37	14.77	16.62	19.17	15.72
राजस्थान	20.62	13.75	18.40	13.74	23.30	13.73
उत्तर प्रदेश	14.74	13.16	16.96	17.96	15.74	13.66
उत्तरांचल	21.14	23.29	20.70	26.01	16.32	15.65
भारत	16.78	15.92	15.64	14.67	17.86	15.06

श्रोत–आर्थिक सर्वेक्षण–2011–12

निबल घरेलू राज्य उत्पाद का प्रतिशत भारत के सापेक्ष

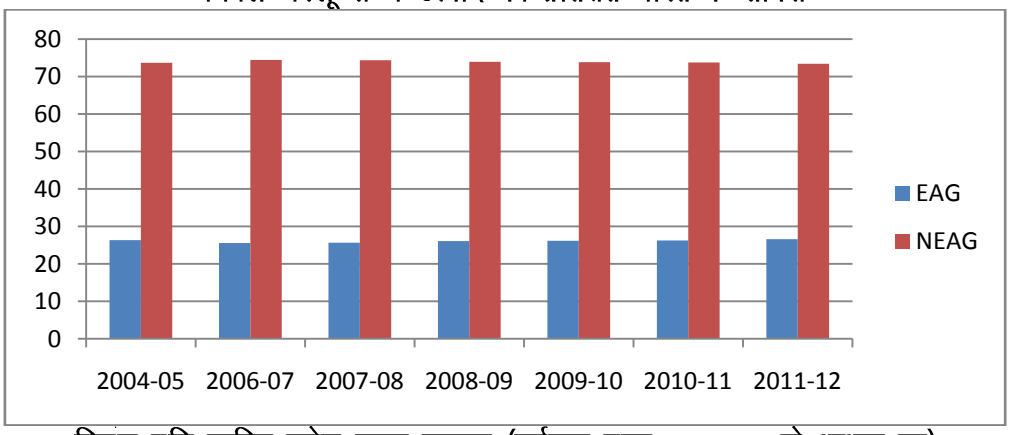

निबल प्रति व्यक्ति घरेलू राज्य उत्पाद (वर्तमान मूल्य 2004–05 के आधार पर)

प्रदेश	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिहार	7914	9967	11051	13728	15548	18928	23435
झारखण्ड	18510	19789	24789	25046	26223	31993	35652
मध्यप्रदेश	15442	19028	20937	25278	26712	32253	38669
छत्तीसगढ़	18559	24800	29385	34360	35121	41167	46573
उड़ीसा	17650	22237	27735	31416	34361	40412	46150
राजस्थान	18565	24055	26882	31279	34962	42434	47506
उत्तर प्रदेश	12950	16031	17785	20422	23661	26903	30052
उत्तरांचल	24726	35111	42619	50657	62885	72093	82193
भारत	24143	31206	35825	40775	46117	53331	60603

स्रोत–आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12

अर्थ"ाास्त्रीयों ने प्रतिव्यक्ति आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात में परिभाषित किया। प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद को आधार मानकर हम स"ाक्त और गैर स"ाक्त राज्यों के उस आर्थिक संकेतक पर ध्यान देंगे, जहाँ जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय आय के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अध्ययन अवधि के दौरान यह पता चलता है कि 2004–05 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद 24143 रूपये था, जो 2011–12 में 39.83 प्रति"ात की वृद्धि के साथ 60603 रूपये हो गया। उत्तराखण्ड को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर्यटन उद्योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ज्यादा विकसित है, शेष सात राज्यों, जो स"ाक्त कार्यदल राज्यों की श्रेणी में आते हैं, प्रति

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking
Vol-II * Issue- XI* April- 2016

व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय से सदैव ही कम रहा है, जबकि गैर स"ाक्त राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद तुलनात्मक रूप से अच्छी है। इसमें भी बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छी प्रतीत होती है। स"ाक्त कार्यदल राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदे"ा दो ऐसे राज्य हैं, जहाँ की प्रतिव्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सापेक्षतः क्रम"ाः 1 तिहाई और आधी रही है, जो वर्तमान परिवे"ा में चिन्ता का विषय है।

सशक्त कार्यदल राज्यों के निबल प्रति व्यक्ति घरेलू राज्य उत्पाद की औसत वृद्धि दर

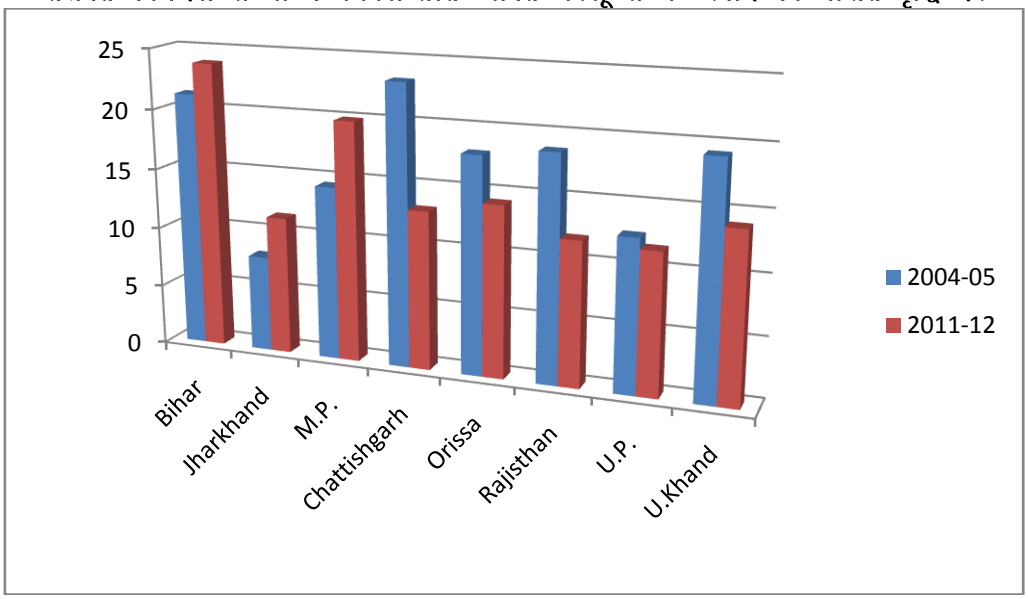

सुझाव

अध्ययन से प्राप्त परिणाम यह द"ार्ाते है कि स"ाक्त कार्यदल राज्यों के ग्रामीण स्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुर आव"यकता है, जिसके लिए सरकारी एवं गैर सकारी उपक्रमों को आगे आना चाहिए। रोजगार परक उद्योगो द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के पलायन को रोका जा सकता है। गर्भवती महिलाओं, नवजात f"ा"ाुओं के प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन एवं f"ाक्षा की लागत में कमी करके हम वाछित परिणाम प्राप्त कर सकते है। स"ाक्त कार्यदल राज्यों को गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों के रुप में परिणित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का पारद"ार्ी एवं भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों, समुदाय और आम जनता में सरकारी एवं गैर सकारी सुविधाओं के प्रति स्वतंत्र चिंतन की क्षमता बलवती करनी होगी।

सामाजिक समस्याओं के नियंत्रण के साथ–साथ स"ाक्त कार्यदल राज्यों की आर्थिक द"ाा को सुधारने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों में निवे"ा में वृद्धि, आधारभूत सुविधाओं (परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाए, f"ाक्षण संस्थाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगार के अवसरों का सृजन इत्यादि) को विकसित करने की आव"यकता है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों का विस्तार किये बगैर हम इन चयनित राज्या के आर्थिक द"ाा में कोई आमूलचूक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। स"ाक्त कार्यदल राज्यों में लघु एवं कुटिर उद्योगों, पर्यटन उद्योग एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के रोजगार सृजन हेतु सरकार को वि"ोष कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। इसके लिए दे"ा के पूँजीपतियों एवं विदे"ाी निवे"ाकों को इन राज्यों में निवे"ा करने का जोखिम उठाना होगा। यह तभी सम्भव है, जब प्रादे"िक सरकारें और क्षेत्रीय लोग इन कार्यों को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इससे कमजोर राज्यों का आर्थिक उन्नयन हागा तथा दे"ा में व्याप्त आर्थिक वि"ामता को नियंत्रित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Benjamm B, Elements of Vital Statistics.
2. Phillp H. Hauser and O.D. Duncon : The study of Population.
3. Heer. David : Problume of Population studies.
4. Dalton : Essay on the Application of a capital to labour.
5. Ragner Nukrsy : Theory of capital Accumalation.